कम करने या उसको बढ़ाने के लिए हम बहुत-सी योजनाएं चला रहे हैं जिन योजनाओं में एक बहुत महत्वपूर्ण योजना 10 अगस्त, 2005 को माननीय वित्त मंत्री महोदय ने घोषित की है और इस आधार पर हम प्रयत्न कर रहे हैं कि जो बैंक का इंटरेस्ट है, क्रैडिट है, उसको कम करने के लिए बहुत से उपाय हम करें। जब ...(व्यवधान)...

श्री दत्ता मेघे: अभी ब्याज क्या ले रहे हैं, वह बताइए।

श्री महावीर प्रसाद: माननीय सदस्य आप अलग से बैठकर बात करिएगा, तब मैं बता दूंगा। अभी मैं इंटरेस्ट के विषय में बता रहा हूं, जैसा माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, उसका जवाब यही है कि हमने माननीय वित्त मंत्री महोदय के संज्ञान में इस चीज़ को डाला है कि कहीं-कहीं बैंक अधिक इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इंटरेस्ट को कम किया जाए, ऐसा हमारा प्रयत्न चल रहा है।

राज्य-वार टेलीफोन-घनत्व

*325. **श्री कृपाल परमार:** †

***श्री सुरेन्द्र लाठ:**

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले वर्ष और इस वर्ष अब तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में टेलीफोन-घनत्व का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों का टेलीफोन-घनत्व, शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम है;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं; और

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर उड़ीसा एवं हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन-घनत्व में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) राज्य-वार टेलीफोन-घनत्व (ग्रामीण और शहरी क्षेत्र) के संबंध में नवीनतम सूचना अर्थात 31.10.2005 तक की सूचना संलग्न विवरण-1 में दी गई है। (नीचे देखिए)

(ख) और (ग) जी, हां। ग्रामीण क्षेत्रों का टेलीफोन-घनत्व शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम रहा है, क्योंकि नेटवर्क का विकास, विशेषकर निजी क्षेत्र में, शहरों पर ज्यादा केन्द्रित था। शहरी क्षेत्रों का बेहतर आर्थिक स्तर और उच्चतर साक्षरता भी इसके सहायक कारक थे।

† यह प्रश्न सभा में श्री कृपाल परमार द्वारा पूछा गया।

(घ) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व में वृद्धि करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि संस्थापित करना।

(ii) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने लैंडलाइन एक्सचेंजों के लिए आउटडोर केबलों को बिछाने के संबंध में दूरी संबंधी मानदंड में छूट देकर उसे 2.5 किमी से बढ़ाकर 5 किमी कर दिया है, जिससे मौजूदा एक्सचेंजों से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक कवरेज दिया जा सकेगा; और

(iii) बीएसएनएल द्वारा डब्ल्यूएलएल (वायरलेस इन लोकल लूप) फोनों को अधिक संख्या में उपलब्ध कराना।

विवरण-I

वर्ष 2004-2005 और 2005-06 के दौरान राज्य-वार टेलीघनत्व (ग्रामीण और शहरी)

क्र० सं०	सर्किल/राज्य का नाम	2004-05 (31.03.2005 की स्थिति के अनुसार)			2005-06 (31.10.2005 की स्थिति के अनुसार)*		
		समग्र	शहरी	ग्रामीण	समग्र	शहरी	ग्रामीण
1	अंडमान व निकोबार	12.63	19.12	9.07	14.6	23.92	9.4
2	आंध्र प्रदेश	9.48	28.53	2.39	10.94	34.13	2.29
3	असम	2.79	16.75	0.63	3.85	24.48	0.62
4	बिहार	2.36	17.63	0.57	3.67	29.95	0.59
5	छतीसगढ़	1.8	6.5	0.54	1.93	7.25	0.47
6	गुजरात	12.73	28.88	2.63	14.23	32.59	2.65
7	हरियाणा	10.83	28.78	2.8	12.51	33.58	2.96
8	हिमाचल प्रदेश	13.12	68.36	6.79	16.47	98.36	7.02
9	जम्मू व कश्मीर	5.09	17.58	0.76	9.2	33.21	0.82
10	झारखंड	2.3	8.42	0.5	2.47	9.11	0.51
11	कर्नाटक	12.19	29.98	2.49	14.05	35.02	2.53
12	केरल	18.77	44.74	9.74	21.08	52.52	10.16
13	मध्य प्रदेश	5.21	17.36	0.66	5.73	19.07	0.71
14	महाराष्ट्र (-) मुंबई	9.96	25.23	2.56	11.41	29.72	2.63

15	पूर्वोत्तर-I	4.33	14.63	1.22	4.98	17.25	1.25
16	पूर्वोत्तर-II	3.66	12.83	1.21	4.33	15.92	1.19
17	उड़ीसा	3.96	19.68	1.04	5.44	28.68	1.02
18	पंजाब	21.94	49.21	5.33	24.48	55.58	5.32
19	राजस्थान	6.12	21.27	1.44	7.7	27.71	1.51
20	तमिलनाडु (-) चेन्नई	11.21	22.96	2.73	12.61	25.68	2.78
21	उत्तरांचल	5.74	17.08	1.63	6.83	20.84	1.7
22	उत्तर प्रदेश	4.06	17.15	0.52	5.51	23.93	0.51
23	पश्चिम बंगाल (-) कोलकाता	2.98	14.85	1.04	4.08	22.96	1.06
24	कोलकाता	24.22	24.22	0	27.07	27.07	0
25	चेन्नई	47.56	47.56	0	53.64	53.64	0
26	दिल्ली	50.94	50.94	0	56.9	56.9	0
27	मुंबई	45.43	45.43	0	49.56	49.56	0
	कुल:	8.95	26.88	1.73	10.53	32.16	1.77

*नवीनतम उपलब्ध आंकड़ा

State-wise teledensity

†*325. SHRI KRIPAL PARMAR:††
SHRI SURENDRA LATH:

Will the Minister of COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) the telephone density in rural and urban areas during the last year and this year till now, State-wise;

(b) whether the telephone density in rural areas is less than that in urban areas;

(c) if so, the details thereof, State-wise and the reasons therefor; and

(d) the steps taken or proposed to be taken by Government to increase the telephone density in rural areas particularly in the rural areas of Orissa and Himachal Pradesh?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI DAYANIDHI MARAN): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

† Original notice of the question was received in Hindi.

†† The question was actually asked on the floor of the House by Shri Kripal Parmar.

Statement

(a) The latest information on State-wise teledensity (rural and urban areas) *i.e.* upto 31.10.2005 is given in the enclosed Statement-I (*See* below).

(b) and (c) Yes Sir. The rural teledensity has been lower than the urban tele-density because the development of network was more urban centric, particularly in the Private Sector. Higher economic and literacy status in the urban areas were also contributing factors.

(d) A number of steps have been taken by the Government to increase the telephone density in rural areas which include the following:

(i) Setting up of the USO Fund by the Government for provision of telephones in the rural areas;

(ii) Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) has relaxed the distance for laying outdoor cables from 2.5 Kms. to 5 Kms. for Landline Exchanges which would facilitate larger coverage in the rural areas from existing exchanges; and

(iii) Increased provision of WLL (Wireless in Local Loop) phones by BSNL.

Statement-I

State-wise Teledensity (Rural and Urban) during 2004-05 and 2005-06

Sl.	Name of Circle/State	2004-05 (As on 31.03.2005)			2005-06 (As on 31.10.2005)*		
		Overall	Urban	Rural	Overall	Urban	Rural
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Andaman & Nicobar	12.63	19.12	9.07	14.6	23.92	9.4
2.	Andhra Pradesh	9.48	28.53	2.39	10.94	34.13	2.29
3.	Assam	2.79	16.75	0.63	3.85	24.48	0.62
4.	Bihar	2.36	17.63	0.57	3.67	29.95	0.59
5.	Chhattisgarh	1.8	6.5	0.54	1.93	7.25	0.47
6.	Gujarat	12.73	28.88	2.63	14.23	32.59	2.65
7.	Haryana	10.83	28.78	2.8	12.51	33.58	2.96
8.	**Himachal Pradesh**	**13.12**	**68.36**	**6.79**	**16.47**	**98.36**	**7.02**
9.	Jammu & Kashmir	5.09	17.58	0.76	9.2	33.21	0.82
10.	Jharkhand	2.3	8.42	0.5	2.47	9.11	0.51
11.	Karnataka	12.19	29.98	2.49	14.05	35.02	2.53
12.	Kerala	18.77	44.74	9.47	21.08	52.52	10.16

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Madhya Pradesh	5.21	17.36	0.66	5.73	19.07	0.71
14.	Maharashtra (-) Mumbai	9.96	25.23	2.56	11.41	29.72	2.63
15.	North East-I	4.33	14.63	1.22	4.98	17.28	1.25
16.	North East-II	3.66	12.83	1.2	4.33	15.92	1.19
17.	**Orissa**	**3.96**	**19.68**	**1.04**	**5.44**	**28.68**	**1.09**
18.	Punjab	21.94	49.21	5.33	24.48	55.58	5.32
19.	Rajasthan	6.12	21.27	1.44	7.7	27.71	1.51
20.	Tamil Nadu (-) Chennai	11.21	22.96	2.73	12.61	25.68	2.78
21.	Uttaranchal	5.74	17.08	1.63	6.83	20.84	1.7
22.	Uttar Pradesh	4.06	17.15	0.52	5.51	23.93	0.51
23.	West Bengal (-) Kolkata	2.98	14.85	1.04	4.08	22.96	1.06
24.	Kolkata	24.22	24.22	0	27.07	27.07	0
25.	Chennai	47.56	47.56	0	53.64	53.64	0
26.	Delhi	50.94	50.94	0	56.9	56.9	0
27.	Mumbai	45.43	45.43	0	49.56	49.56	0
	TOTAL	8.95	26.88	1.73	10.53	32.16	1.77

**latest available*

श्री कृपाल परमार: माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री ने जो उत्तर दिया है, उसमें उन्होंने 2004-05 के तुलनात्मक आंकड़े दिए हैं। मैंने प्रश्न में पूछा था कि सरकार ग्रामीण क्षेत्र में टेलीफोन के घनत्व को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर रही है? उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं, वे बहुत रोचक भी हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक साल में आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, पूर्वोत्तर और पंजाब में ग्रामीण क्षेत्रों में घनत्व में गिरावट आई है। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हम उसमें बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं और इन्हीं के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल से इस साल में, चाहे वह कमी मार्जिनल है, कम है, लेकिन जब प्रयास उसको बढ़ाने का किया जा रहा है, तो उसमें कमी आने के कारण क्या हैं?

SHRI DAYANIDHI MARAN: Sir, the hon. Member has asked about the tele-density of urban and rural areas and I have got the figures with me. The figures are varying. We have been making efforts to increase the tele-density all over and change the picture of the country. It is a fact that the urban tele-density is always on the rise. When we compare it with urban tele-density, the rural tele-density is little low. If we compare Andhra Pradesh, the figure of urban tele-density has increased from 28.53 per cent to 34.13 per cent, whereas the rural tele-density has come down from 2.39 per cent to 2.29 per cent. Sir, I feel, basically it is a roll over thing and I will get back to the hon. Member on this particular issue.

श्री कृपाल परमार: सभापति महोदय, इन मामलों के मुताबिक पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश का टेलीफोन घनत्व देशभर में बेहतर है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश टेलीफोन खराब रहते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं, हर जगह उनकी भारी कमी है। टेलीफोन खराब होने पर हफ्तों, महीनों तक कम्पलेंट अटैंड नहीं की जाती है और टेलीफोन ठीक नहीं होते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे? इसके साथ ही मेरे प्रश्न का अंतिम भाग यह है कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में जो WLL सिस्टम लगा रहे हैं, उसमें कनैक्टिविटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है, इसको दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है?

SHRI DAYANIDHI MARAN: Sir, through you, if the hon. Member can give me specific complaints, I can definitely answer on specific complaints. Overall, we have been able to match any complaint received and can give data on any specific area or specific district whichever the hon. Member requires. We have been making efforts to increase the rural tele-density. In fact, we are now using the USO fund to increase it. We are seeing that more private operators also come for bidding for the USO fund to provide telecom services in the rural areas. It is an on-going measure.

श्री सुरेन्द्र लाठ: सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में जो आंकड़े दिए हैं, वे निराशाजनक हैं। उन्होंने वर्ष 2004-05 में ग्रामीण क्षेत्र में 2003-04 से 2004-05 में जो बढ़त दिखाई है, वह सिर्फ 1.73 से 1.77 है। इससे यह पता चलता है कि टेलीफोन सेवा के विकास की जो गति है, वह ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत धीमी है और हमने दसवीं पंचवर्षीय योजना तक जो लक्ष्य रखा है कि प्रत्येक गांव तक टेलीफोन सेवा पहुंच पाएगी, यह किस प्रकार पहुंच पाएगी? इस गति से तो ऐसा लगता है कि यह नहीं पहुंच पाएगी। इसके लिए क्या मंत्री महोदय कोई विशेष योजना लाने के बारे में सोच रहे हैं? मेरे प्रश्न का जो बी पार्ट है ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: दूसरा नहीं, बस एक ही। पहले वे इतना ही जवाब दे दें तो... (**व्यवधान**).

श्री सुरेन्द्र लाठ: सर, छोटा-सा है, बहुत-छोटा सा है। मंत्री महोदय ने WLL के बारे में कहा है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में WLL के माध्यम से टेलीफोन सेवा का विस्तार कर रहे हैं। महोदय, उड़ीसा में WLL की सेवाएं आरंभ की गई हैं, किन्तु अभी जो अनुभव प्राप्त हुआ है कि

अधिकांश जगहों पर WLL की सेवाएं बंद होती जा रही हैं। मैं मंत्री महोदय जी से यह जानना चाहूंगा कि उड़ीसा में अब तक कितने क्षेत्रों में WLL की सेवाएं प्रारंभ की गई हैं और WLL के माध्यम से कितने टेलीफोन दिए गए हैं, कृपया मंत्री महोदय यह बताएं?

SHRI DAYANIDHI MARAN: Sir, in fact, I can say that in the State of Orissa, the waiting list as for this date, 30.11.2005 is 37624. The BSNL alone is planning to add 7,95,000 new connections in this financial year. This is an ongoing process and if hon. Member needs specific details on WLL, I will send it to him.

SHRIMATI S.G. INDIRA: Sir, as the Minister is well aware, the telephone came to India a century back, but the cellphone was introduced only a decade back. But, the cellphones' growth saw tremendous advertisement in terms of density. We are talking about density. The growth of landline connections has been declining nowadays. Therefore, I would like to ask the hon. Minister what are the steps he is going to take to increase the landline connections in the rural and also in the urban areas.

SHRI DAYANIDHI MARAN: Sir, hon. Member has asked a very valid question. It is a fact that now the landline connections have been literally growing at very slow rate. Increase in landline connections is very marginal. The reason being the cost of landline is very expensive. The cost goes up to Rs. 25,000 for single fixed landline whereas that for a cellphone is only Rs.3,000 for any company to install. Moreover, it is much faster to provide cellular or wireless service. In case of landline service, it is very slow. But, even now, BSNL is providing landline service. But, the priority for customers the market demand is more for cellular.

श्री राजू परमार: सभापति जी, अभी माननीय मंत्री महोदय ने जिक्र किया है कि ग्रामीण क्षेत्र में प्राइवेट ऑपरेटर्स भी टेलीफोन लगा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि डिपार्टमेंट की तरफ से जो कोटा प्राइवेट ऑपरेटर्स को दिया गया है कि इतने फोन आप गांवों में लगाइए, वह कोटा उन्होंने पूरा किया है या नहीं? मेरी जानकारी के मुताबिक प्राइवेट ऑपरेटर्स कई जगह landline नहीं लगा रहे हैं। क्या इसके बारे में माननीय मंत्री जी जानकारी देंगे?

SHRI DAYANIDHI MARAN: Sir, let me say since the year 2002, the compulsory roll-out for private operators has been relaxed. It was based on the TRAI's recommendation that we went into a new system—Universal Service Obligation (USO) Fund. From that time onwards, we decided that a part of licence fee—5 per cent of licence fee, which is nearly 50 per cent—will be used to promote the rural obligation. And, in fact, now, we really have allocated roughly about Rs.3000 crores for the USO fund for the roll-out in the rural areas, area and nearly Rs. 2785 crores of this amount has been used for the USO fund.

SHRI ROBERT KHARSHIING: Mr. Chairman, Sir, last year, during the winter session, the hon. Minister, in reply to a supplementary question in this august House, had agreed to convene a meeting of North-East M.P.s to review communications in that area. I am extremely grateful that he kept his promise and we had an extremely fruitful meeting. One year later, Sir, would the Minister convene another meeting so that we can have follow-up on the progress made by him?

SHRI DAYANIDHI MARAN: I thank the hon. Member. Definitely, Sir.

MR. CHAIRMAN: Next question....*(Interruptions)*...

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, we propose a half-an-hour discussion.

श्री सभापति: आप मूव कर दीजिए।

Nehru Yuva Kendras in Punjab

*326. SHRI DHARAM PAL SABHARWAL: Will the Minister of YOUTH AFFAIRS AND SPORTS be pleased to state:

(a) the number of Nehru Yuva Kendras functioning in Punjab at present, location-wise; and

(b) the details of the programmes being run by these Kendras during the last three years and the current year alongwith performance of these Kendras?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SHRI OSCAR FERNANDES): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.